



# Skill Development Programme

## For Answer Writing

### International Relation

### Model Answer (Full Test)

DATE : 20-June-2018

TIME : 06:30 pm

#### मुख्य परीक्षा

1. वर्तमान वैश्वीकरण की परिस्थिति में शक्ति संतुलन की अवधारणा का परीक्षण कीजिए।

( 150 शब्द, 10 अंक )

Examine the concept of Balance of Power in context of present globalisation.

(150 Words, 10 Marks)

### MODEL ANSWER

**उत्तर-** शक्ति संतुलन का सिद्धांत शक्ति और शक्ति संघर्ष की अवधारणा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दो देशों/गुटों के बीच शक्ति का ऐसा वितरण जिससे युद्ध की संभावना कम हो जाए। ऐसी व्यवस्था नीति एवं अवस्था को शक्ति संतुलन कहा जाता है।

शक्ति संतुलन अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता उत्पन्न करता है, जो विश्वयुद्ध जैसी घटनाओं की संभावना कमतर करता है। जिससे शांति बनी रहती है। शक्ति संतुलन लागू होने से छोटे देशों की सम्प्रभुता की सुरक्षा बनी रहती है साथ ही ये देश इन महाशक्तियों से विभिन्न प्रकार की लाभ उठाते हैं। इस व्यवस्था में प्रतियोगी माहौल बना रहता है, जिससे तकनीकी विकास व नए अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है।

शक्ति संतुलन का सिद्धांत शक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है साथ ही यह गुटबंदी को बढ़ावा देता है। साथ ही शास्त्रीकरण की दौड़ को बढ़ावा मिलता है, जिससे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इस व्यवस्था में विश्व/क्षेत्र दो खेमों में बंट जाता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध कमज़ोर पड़ते हैं। सैन्य संगठनों का निर्माण होता है और क्षेत्रीय-आर्थिक संगठन की स्थिति कमज़ोर होती है।

#### निष्कर्ष-

यह माना जाता है कि शक्ति संतुलन को प्राथमिकता देने वाले राजनय के कारण दी 19वीं सदी में, यूरोप युद्ध से बचा रहा था। संतुलन की अवधारणा तब तक जारी रहती है, जब तक कि राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष पूरी तरह से अप्रचलित है और न ही मृत। हालांकि इसकी भूमिका वैश्विक प्रयोग से शक्ति प्रबंधन के क्षेत्रीय प्रयोग में बदल गई है।

\* \* \*





# Skill Development Programme

## For Answer Writing International Relation Model Answer (Full Test)

DATE : 20-June-2018

TIME : 06:30 pm

### मुख्य परीक्षा

2. NPT के प्रावधानों को स्पष्ट करें। भारत किन कारणों से NPT पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है? (250 शब्द, 15 अंक)

Explain the provisions of NPT. Why India can not sign NPT?

(250 Words, 15 Marks)

### MODEL ANSWER

**उत्तर-** परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ-साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा परमाणु शस्त्रों के प्रसार और नियंत्रण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और इसी प्रस्ताव के तहत 1968 में अमेरिका, बिट्रेन, सोवियत संघ द्वारा इस संधि को तैयार किया गया और 1970 से इस संधि को लागू कर दिया गया। अभी तक लगभग 190 देशों ने हस्ताक्षर किया है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, अथवा संधि से बाहर निकल गये हैं।

#### प्रावधान-

- इस संधि में देशों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र (NWS : Nuclear Weapon Status) और गैर परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र (NNWS (Non Nuclear Weapon State))। जिन देशों ने 1 जनवरी, 1968 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया वे NWS तथा इसके बाद परीक्षण करने वाले राष्ट्रों को NNWS कहा जाता है।
- जो देश NNWS के रूप में शामिल है, वे ना तो परमाणु बम बनाएंगे न ही NWS उन्हें परमाणु बम देंगे।
- NNWS को NWS सभी प्रकार की तकनीकी मदद करेंगे, जैसे- बिजली उत्पादन, चिकित्सा, पर्यावरण आदि संदर्भों में।
- NNWS के विरुद्ध NWS परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे।
- सभी सदस्य देशों पर बाध्यता होगी की परमाणु मदों का हस्तान्तरण तभी करेंगे जब अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एंजेंसी अनुमति प्रदान करें।

#### भारत और NPT :

- भारत निम्न कारणों से NPT पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है-
- भारत के अनुसार यह संधि भेदभावमूलक है, क्योंकि इससे विश्व को 2 भागों में बांटा गया है, जो स्थायी असमानता को स्वीकार करता है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों का समान दर्जा प्रदान करता है।
  - इस संधि में क्षेत्रिक प्रसार को रोकने की बात की गई है, लेकिन लम्बवत् प्रसार को नहीं रोकता है।
  - इस संधि में कहा गया है कि किसी देश पर परमाणु हमला होने की स्थिति में UNO द्वारा उसकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन UNO में भी P-5 के देश ही स्थायी सदस्य हैं।
  - भारत का मानना है कि NPT संधि का स्वयं चीन, अमेरिका जैसे- राष्ट्रों ने उल्लंघन किया है। उदाहरणस्वरूप अमेरिका ने इजराइल, चीन ने पाकिस्तान आदि को परमाणु सहायता प्रदान की।

\* \* \*





# Skill Development Programme

## For Answer Writing International Relation Model Answer (Full Test)

DATE : 20-June-2018

TIME : 06:30 pm

### मुख्य परीक्षा

3. भारत की परमाणु नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करें। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण करें।  
(250 शब्द, 15 अंक)

**Explain the provisions of Indian Nuclear Policy. Examine its relevance in present.**

(250 Words, 15 Marks)

### MODEL ANSWER

उत्तर- भारत की परमाणु नीति को जड़े शांति और शांतिवाद में है। इसी तरह से आज तक स्वीकार्य वर्षों से परमाणु नीति का संक्रमण से अब तक एक शानदार बदलाव आया है। पोखरण-II के बाद 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर परमाणु नीति का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे तात्कालिक प्रधानमंत्री के सचिव बृजेश मिश्रा द्वारा जारी किया गया।

#### प्रावधान-

- यदि कोई देश भारत के प्रति परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है, तो भारत असमान रूप से या दण्डनीय प्रतिरोध के साथ प्रयोग करेगा।
- परमाणु नीति शांति एवं सुरक्षा दोनों उद्देश्यों को धारण करती है।
- भारत परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं करेगा अर्थात् स्वैच्छिक रोक लगा लिया है, किन्तु भारत परमाणु हथियारों के साथ प्रतिशोध करने के विकल्प के साथ आ सकता है यदि भारत के खिलाफ कोई बड़ा हमला जैविक या रासायनिक हथियार द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- न्यूनतम आवश्यक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता तक परमाणु हथियारों का विकास करेगा। अर्थात् उतना परमाणु क्षमता रखेगा जितना अन्य राष्ट्रों को विश्वसनीय रूप से हमला करने से रोक सके।
- परमाणु शक्ति रहित देश के खिलाफ प्रयोग नहीं करेगा।
- भारत पूर्ण निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है।

वर्तमान में भारत की परमाणु नीति में विकल्प है, जिस में समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही जिम्मेदार परमाणु शक्ति राष्ट्र होने के कारण नागरिक नियंत्रण स्थापित किया गया है। इसमें राजनीतिक एवं कार्यकारी परिषद् दोनों मिल कर निर्णय लेगी। साथ ही भारत के पड़ोस में चीन, पाकिस्तान परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन गए। ऐसे में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

\* \* \*





# Skill Development Programme

## For Answer Writing International Relation Model Answer (Full Test)

DATE : 20-June-2018

TIME : 06:30 pm

- मुख्य परीक्षा
4. पूँजीवाद क्या है? यह समाजवादी अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट करें।  
( 150 शब्द, 10 अंक )
- What is Capitalism? How it is different from Socialist economy? Explain.**  
(150 Words, 10 Marks)

### MODEL ANSWER

**उत्तर-** पूँजीवाद सामान्यतः उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं, जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, जहाँ 'व्यक्तिगत' का अर्थ किसी एक व्यक्ति से अथवा व्यक्तिगत समूहों से होता है। इस प्रकार पूँजीवाद एक आर्थिक पद्धति है, जिसमें पूँजी के स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्यों के अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है।

पूँजीवाद और समाजवाद के बीच मूलभूत अंतर अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का दायरा है। पूँजीवादी आर्थिक मॉडल नवाचार और धन सृजन करने के लिए निःशुल्क बाजार की स्थितियों की अनुमति देता है। समाजवादी आधारित अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत आर्थिक योजना के तत्वों को शामिल किया गया है, जिसका उपयोग अनुरूपता सुनिश्चित करने और अवसरों और आर्थिक परिणामों की समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था संपत्ति और व्यवसायों में व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में, राज्य उत्पादन के प्रमुख साधनों का मालिक है और नियंत्रण करता है। कुछ समाजवादी आर्थिक मॉडल में, कार्यकर्ता सहकारी समितियों के उत्पादन में सर्वोच्च हैं।

#### निष्कर्ष-

इस प्रकार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि असमानता एक प्रेरणा शक्ति है, जो नवाचार को प्रोत्साहित करती है, जो फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। वही समाजवादी मॉडल की प्राथमिक चिंता अमीर से गरीबों और निष्पक्षता से धन और सांसाधनों का पुनर्वितरण है तथा अवसर और समानता में समानता सुनिश्चित करने के लिए है।

उपर्युक्त दोनों अर्थव्यवस्थाओं में कोई भी एक को अपनाना, एक देश के लिए समस्या का कारण बन सकता है, लेकिन इसी का समन्वय दृष्टिकोण मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के लिए उपर्युक्त है।

\* \* \*



# Skill Development Programme

## For Answer Writing

### International Relation

### Model Answer (Full Test)

DATE : 20-June-2018

TIME : 06:30 pm

#### मुख्य परीक्षा

5. गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता का परीक्षण करें।

( 250 शब्द, 15 अंक )

Examine the relevance of Non-Aligned Movement in present.

(250 Words, 15 Marks)

### MODEL ANSWER

उत्तर- गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद द्वि-ध्रवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उदय के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एवं विश्व के अन्य उन देशों को मिलाकर किया गया, जो तत्कालीन समय में उपनिवेशी समस्याओं से गुजर रहे थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से इस आंदोलन का शुभारम्भ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्त्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया।

#### वर्तमान में प्रासंगिकता-

- गुट निरपेक्ष आंदोलन 120 देशों (अफ्रीका-53, एशिया-39, लैटिन अमेरिका-26 व यूरोप के 2 देश बेलारूस एवं अजरबैजान) का आंदोलन है। अतः इस व्यवस्था के माध्यम से दक्षिण के देश आपस में एकीकृत हो सकते हैं और पूँजीवाद राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, जैसे कि वेनेजुएला सम्मेलन में दिखाई दिया, जिसके मुख्य विषय विकास के लिए शांति, सम्प्रभुता एवं एकता रखा गया।
- वर्तमान में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक शोषण अभी भी जारी है।
- गुट निरपेक्ष देश पंचशील के पांच सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, जो हैं- अनाक्रमण, समानता एवं पारस्परिक लाभ, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक-दूसरे की सम्प्रभुता एवं प्रादेशिक अखण्डता का आदर एवं शांतिमय सह अस्तित्व जो गुटनिरेक्षता के मुख्य आधार कहे जा सकते हैं।
- गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ ऐसे देश हैं, जो वास्तव में गुट निरपेक्ष प्रवृत्ति नहीं रखते जैसे पाकिस्तान, मिस्र नाटो के सहयोगी शब्द बन गए।
- गुट निरपेक्ष आंदोलन में निरंतर गुटबंदी बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष के देश सम्मेलनों में अपने द्विपक्षीय मुद्दों को ही ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे नाइजीरिया एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच विवाद।
- दक्षिण के देश विकाशील एवं गरीब हैं। इसलिए ये उत्तर का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी पूँजी एवं तकनीक पर निर्भर रहते हैं तथा किसी भी विषयगत मामलों में खुलकर विरोध नहीं कर पाते।

इस प्रकार NAM के माध्यम से तृतीय विश्व के देश शीतयुद्ध की चपेट से बचने में सफल रहे। गुट निरपेक्ष संगठन तो हमारे ही बृहद विश्व के सपने का हिस्सा है। हो सकता है कि आज की विदेश नीति की व्यस्तता को देखते हुए भले ही इस संगठन की सदस्यता हमें अर्थपूर्ण न लगे, परन्तु इस परिवर्तनशील दौर में विश्व समुदाय को साथ लेकर ही चलना ही दूरदर्शिता है।

\* \* \*





# Skill Development Programme

## For Answer Writing

### International Relation

### Model Answer (Full Test)

DATE : 20-June-2018

TIME : 06:30 pm

#### मुख्य परीक्षा

6. भारत की विदेश नीति में निरंतरता तथा परिवर्तनशीलता को उदाहरण सहित स्पष्ट करें।

( 250 शब्द, 15 अंक )

**Explain the consistency and volatility in Indian Foreign Policy with examples.**

(250 Words, 15 Marks)

#### MODEL ANSWER

उत्तर- विदेश नीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और नहीं दुश्मन। अगर कुछ शाश्वत रहता है, तो वह है राष्ट्रीय हित। इन अर्थों में विदेश नीति राष्ट्रीय हित से अपरिहार्य रूप से जुड़ी होती है। इस कारण अगर हित बदलते हैं तो विदेश नीति में परिवर्तन के तत्व दिखते हैं और नहीं बदलती हैं तो निरंतरता को तत्व देखते जा सकते हैं।

आजादी के समय स्वतंत्र भारत को अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखनी थी। इसी कारण बिना गुटों के भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया और स्वतंत्र विदेश नीति अखियार की। इसमें भारत के आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक हित शांतीपूर्ण विश्व, उपनिवेशवाद-साम्राज्यवाद विभेद, रंगभेद की नीति का अंत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रजातांत्रीकरण मानवाधिकार इत्यादि पर टिका था।

श्रीमती गांधी के काल में भारत खाद्यान्न संकट तथा दो पड़ोसियों के साथ युद्ध का दबाव, गरीबी, भूखमरी इत्यादि से घिरा हुआ था। अतः श्रीमती गांधी की विदेश नीति यथार्थवाद की ओर झुकी तथा चीन-पाक-अमेरिका को प्रतिसंतुलित करने के लिए रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे होने लगे।

आज भी भारत के एक ईस्ट नीति एक्ट वेस्ट नीति, दक्षिण-चीन सागर विवाद में चतुष्कोणीय नीति, इत्यादि भारत के वर्तमान हित से जुड़े हैं। अतः इस रूप में भारत की विदेश नीति में निरंतरता के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं।

हालांकि वर्तमान में परिवर्तन के तत्व भी देखे जा रहे हैं यथा-

- बड़े देशों के साथ अब छोटे देशों से भी समान स्तर पर संबंध निर्धारित हो रहे हैं। यथा- सेशल्सा, पापुआ न्यूगिनी, मौरीशस आदि।
- वर्तमान भारतीय विदेश नीति में संतुलनकारी यथार्थवाद देखने को मिल रहा है। यथा- एक और जहाँ भारत का संबंध ईराइल, सउदी अरब और ईरान तीनों से बेहतर हैं। वही अमेरिका रूस के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
- वर्तमान भारतीय विदेश नीति में अधिक मुद्दे को द्रव्य में है। यथा- चीन के साथ संबंध।
- प्रवासी लोगों की भूमिका विदेश नीति में बढ़ी है, जो दो राष्ट्रों के साथ संबंधों को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यथा- भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में।
- विदेश नीति में तीव्रता भी देखने को मिल रही है। यथा MoU (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित होने के बाद इनका क्रियान्वयन तुरन्त हो रहा है।
- भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रियता देखी जा रही है। यथा पर्यावरण के संदर्भ में सोलर अलायंस आतंवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत को एकजूट करना।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति में जहाँ एक ओर नेहरू गुण का आदर्श तथा श्रीमती गांधी युग का यथार्थ आज भी बना हुआ है, वहीं इसकी ओर बदलती परिस्थितियों के कारण परिवर्तन के तत्व भी अपरिहार्य रूप से देखें जा रहे हैं।

\* \* \*